

**Demand to give Green Bonus of ₹ 2000 crore to Uttarakhand
for overall development of the State**

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड) : महोदय, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का 1.63 प्रतिशत है, लेकिन राज्य का वन क्षेत्र 4.53 प्रतिशत अधिक है। राज्य का तीन-चौथाई हिस्सा जंगलों, ग्लेशियरों तथा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इन परिस्थितियों में विकास कार्य करना आसान काम नहीं है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य में 1000 मीटर की ऊंचाई पर उगे हुए पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध है। इस ऊंचाई पर उगे पेड़ों को काटना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण राज्य का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में 16 प्रतिशत वन भी हैं, जिनके संरक्षण के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है।

अर्जेंटीना में विश्व वानिकी कांग्रेस 2009 में प्रस्तुत अपने पत्र में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ने अपने अनुमान में कहा है कि पर्यावरण संरक्षण पर राज्य के 32,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं।

हमारे राज्य उत्तराखंड को भी इसी प्रकार ग्रीन बोनस की दरकार है क्योंकि पिछले साल राज्य में प्राकृतिक आपदा में भारी नुकसान, लोगों की सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च, विद्युत परियोजनाओं का बंद होना तथा प्राइवेट पूंजी निवेश की कमी राज्य के विकास में बाधा डाल रहे हैं।

पिछले साल की प्राकृतिक आपदा ने राज्य में भारी नुकसान किया है। इससे राज्य के पर्यटन पर भारी प्रभाव पड़ा है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि 13वें वित्त आयोग ने राज्य को ग्रीन बोनस देने की अनुशंसा की थी।

राज्य को 2,000 करोड़ ग्रीन बोनस दिया जाए जिससे कि राज्य अपने बहुमुखी विकास के मार्ग पर निरंतर बढ़ता रहे। धन्यवाद।

**Demand to hold the Civil Services Examination conducted
by U.P.S.C. in all regional languages**

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (Tamil Nadu): Sir, during the last few weeks, we had a ranging controversy over the C.S.A.T. examination, being conducted by the UPSC. The aspirant-students are undergoing severe mental agony because in another two weeks' time, they have to undertake that examination.

That being so, the students of Tamil Nadu, in particular, and students of other regions of different States, in general, are put to undue hardship and unfair disadvantage because the examination is being conducted only in Hindi and English.

This aberration must be corrected immediately and the unfair disadvantage to the Tamil students and the students of other regions must be eliminated.

Our country believes in 'unity in diversity', and India is having a federal setup. So, all the languages and cultures of all the regions of our country must be respected and regarded as equal.